



Maurice Hindus predicted the India-China economic divide

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Metro

जी.एस.टी. 2.0 (रिफॉर्म्स का नया दौर) केवल आशा पर निर्भर नहीं है

वित्त मंत्री आशा कर रही हैं कि इन रिफॉर्म्स के कारण रोजमर्रा का सामान सस्ता होगा, और डिमाण्ड (मांग) बढ़ेगी

-अंजन गंध-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-

नई दिल्ली, 4 सितम्बर। जीएसटी काउन्सिल द्वारा किए गए सुधार पूरे देश के लिए एक बड़ा बदल जैसा कदम है। यह कदम न तो एक केंद्र सरकार वर्किंग राज्यों के बजट को भी बदल करने वाला अहम कारबने गा। माल और सेवा कर यानी जीएसटी ने सभी अप्रत्यक्ष करों (इनडायरेक्ट टैक्सों) को मिलाकर एक साथ कर दिया बनाया था और अब यह केंद्र व राज्यों दोनों को कुल आय का बड़ा हिस्सा है।

दरअसल, जीएसटी की दरों में व्यापक बदलाव और कर की श्रेणियों को बदलने की पाठें यहीं तक हैं। सबसे पहले, यह कर दरों की श्रेणियों को साल बनाने और घटाने के बाद को पूरा करता है।

यह सुनहरा, 2017 में जीएसटी लागू करते समय शुरू हुए व्यापक कर सुधारों का हिस्सा है। उस समय देश में केंद्र और राज्यों की कई अलग-अलग कर व्यवस्थाएँ थीं जिन्हें मिलाकर एक समान “कर प्रणाली” यानी जी.एस.टी., बनाई गई।

- विदेश में (विशेषकर अमेरिका में) ऊची टैरिफ के कारण भारतीय सामान के निर्यात को धक्का लगेगा। वित्त मंत्री चाहती हैं कि विदेशों में मांग घटने से व्यापार में आई कमी की भरपाई, देश में स्थानीय खपत बढ़ने से पूरी की जा सकेगी।
- टैक्स घटा कर, “इन्टर्नल डिमाण्ड” बढ़ाने का फार्मूला कई देश पहले ही अजमा चुके हैं। उदाहरण के लिये, अमेरिका में भी राष्ट्रपति रीगन की सरकार ने स्थानीय टैक्स काफी घटाये थे, तथा इससे देश में “इन्टर्नल डिमाण्ड” आंकलन से भी ज्यादा बढ़ी थी, और अमेरिका की इकॉनमी के बारे-न्यारे हो गये थे।
- पर अगर भारतीय उद्योगपतियों ने बढ़ती डिमाण्ड की पूर्ति के लिये, नया इन्वेस्टमेंट करके औद्योगिक क्षमता नहीं बढ़ाई, तो सप्लाई की पूर्ति नहीं कर पायेंगे और मंहगाई बढ़ेगी, और इकॉनमी में उल्टा चक्रकर घूमने लगेगा और अगर इकॉनमी इस द्वृहरचना में फंस गई तो उससे उबरना बहुत मुश्किल होगा।

उस समय बाद किया गया था कि धोरे इन्हें दो स्लैब में समेटा जाएगा। केवल दो टैक्स स्लैब होंगे, लेकिन वर्तमान सुधार उसी दिशा में कदम है व्यवहारिक कारों से चार स्लैब लागू। जिसमें अब 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और एक अलग, 40

प्रतिशत का “सिन टैक्स” शामिल है। औसतन, जीएसटी केंद्र और राज्यों की कुल आय का लगभग 44 प्रतिशत है, तथा राज्यों की आय में इकाका हिस्सा और भी अधिक है। इसलिए दो दरों में बदलाव से राज्यों की विविध रिस्ट्रिक्शन केंद्र से ज्यादा प्रभावित हो सकती है। चूंकि जीएसटी ने दरों के बदलाव तय करती है और न तो केंद्र और न ही राज्य इन्हें अकेले बदल सकते हैं, इसलिए ये घोषणाएँ एक ठोस से व्याप्रांग ढांचा देती हैं जिसके भीतर बजट बनाना अनिवार्य होगा।

ए.जी.एस.टी. सुधारों की घोषणा से बजट बनाने के लिए एक आधार तय हो गया है। जीएसटी 2.0 कहलाने वाले इस स्लैब सुधार की घोषणा उपराने बजट बदलावों जैसी लागी, जहां कर में बदलाव के असर से रोजपानी की चीजों की कीमतें ऊपर नीचे होती थीं, इसरेट महिने, बीजल सप्लाई सकती है। जीएसटी के बाद अदालत ने याचिकारी की अवधि को बढ़ावा दिया है। अदालत के असर से रोजपानी की चीजों की कीमतें ऊपर नीचे होती थीं, इसरेट महिने, बीजल सप्लाई सकती है। जीएसटी के बाद अदालत ने याचिकारी की अवधि को बढ़ावा दिया है। अदालत के असर से रोजपानी की चीजों की कीमतें ऊपर नीचे होती थीं, इसरेट महिने, बीजल सप्लाई सकती है। जीएसटी के बाद अदालत ने याचिकारी की अवधि को बढ़ावा दिया है।

सवाल है कि अप्पी ये बदलाव क्यों? दरअसल, स्लैब घटाने और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जमानती अपराध पर महिला आरोपियों को 43 दिन जेल में रखना खेदजनक

जयपुर, 4 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानती अपराध होने के बावजूद, महिला आरोपियों का जमानत प्राविधिक निरसन कर जेल भेजने तथा उन्हें 43 दिन तक जेल में रखने पर खेद जागाया है। इसके साथ ही, अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय की, और से पेश स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होते हुए रोजस्ट्रार को आदेश दिए हैं कि वे प्रकरण की ओसान, जीएसटी केंद्र और राज्यों की कारणीयता की विवादित रिस्ट्रिक्शन केंद्र से ज्यादा प्रभावित हो सकती है। चूंकि जीएसटी की दरों के कार्यकाल तय करती है और न तो केंद्र और न ही राज्य इन्हें अकेले बदल सकते हैं, इसलिए ये घोषणाएँ एक ठोस से व्याप्रांग ढांचा देती हैं जिसके भीतर बजट बनाना अनिवार्य होगा।

हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारी मशीनी अंदाज में जमानत प्रार्थना पत्र नहीं निपायाये।

जानकारी जिले के गार्डिनिंग जन जक को दें। व्यापक अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वे संबंधित जांच अधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांग कर आगामी कार्यवाही में देखा गया है। एक गंभीर अदालत ने याचिकारी की अवधि को बढ़ावा दिया है कि यदि उन्हें तात्पात्र है कि प्रकरण को प्राप्त करने के बाद उपरान की एकलपत्री ने ये आदेश कुमार उपरान की एकलपत्री ने ये आदेश मानूस और संघर्षक और इंद्र वर्मा की याचिकारी को प्राप्त करने हैं। एकलपत्री ने ये आदेश मानूस और संघर्षक और इंद्र वर्मा की याचिकारी को प्राप्त करने हैं।

सुनवाई के दौरान, न्यायिक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने माना उत्तरी राज्यों में भारी बाद का प्रमुख कारण पेड़ों की अवैध कटाई है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मीडिया रिपोर्ट्स में बाद में लकड़ी के बड़े-बड़े लट्ठे बहते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लगता है पहाड़ों पर पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-

नई दिल्ली, 4 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट के विनोदचंद्रन की बैठक ने इस बारे में सॉलिसिटर जनरल तुशर येहाजा को संबोधित करते हुए कहा, ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठे दिख रहे हैं इससे लगता है पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है।

एस जी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट का आश्वासन दिया कि वे इस बारे में जल्दी से जल्दी पर्यावरण मंत्रालय व राज्यों के मुख्य सचिवों से बात करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवर्फ़ और जस्टिस के विनोदचंद्रन की बैठक ने इस बारे में सॉलिसिटर जनरल तुशर येहाजा को संबोधित करते हुए कहा, ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठे दिख रहे हैं इससे लगता है पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है।

पीड़ी ने केंद्र सरकार को पर्यावरण मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से - और साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एपीडीएम) तथा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उत्तराखण्ड सरकार को नोटिस भेजकर दो सप्लाइ के भीतर जबाब मांगा है। उसके बाद आगे सुनवाई होगी।

(एनडीएमए) तथा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और जम्मू-कश्मीर की प्रदेश, नैशनल हाइवेरेज अथोरिटी, नैशनल हाइवेरेज अथोरिटी ऑफ इंडिया तथा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उत्तराखण्ड सरकार को नोटिस भेजकर दो सप्लाइ के भीतर जबाब मांगा है। इसके बाद इस मामले की कहा है कि इसके बाद इस मामले की आगे सुनवाई होगी।

मुख्य न्यायाधीश ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इसके बाद इस मामले की आगे सुनवाई होगी।

मुख्य न्यायाधीश ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय, जलशक्ति विभाग, नैशनल हाइवेरेज अथोरिटी, नैशनल हाइवेरेज अथोरिटी ऑफ इंडिया तथा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उत्तराखण्ड सरकार को नोटिस भेजकर दो सप्लाइ के भीतर जबाब मांगा है। उसके बाद आगे सुनवाई होगी।

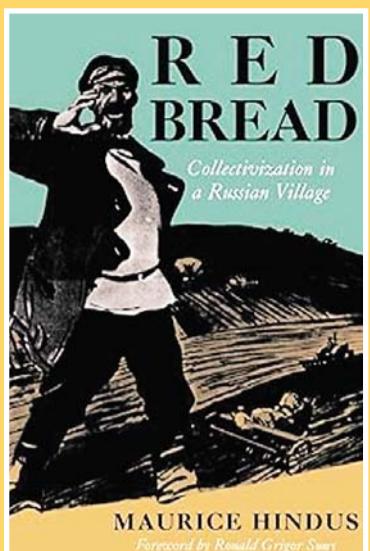
सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय, जलशक्ति विभाग, नैशनल हाइवेरेज अथोरिटी, नैशनल हाइवेरेज अथोरिटी ऑफ इंडिया तथा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उत्तराखण्ड सरकार को नोटिस भेजकर दो सप्लाइ के भीतर जबाब मांगा है। उसके बाद आगे सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट के मु

#FEAR

"I see you Fear"

Fear Lives in Future 'What Ifs,'
But You Don't Have To



"You have been
fighting with
your fear."

Accept it and see
what happens. Just sit
silently and accept it,
and say, "I have fear,
so I am fear."

OSHO



Fear is a powerful emotion, and a deeply human one. But most often, fear isn't rooted in our present reality. It lives in the 'what if's' of the future.

What if I lose everything?

What if they reject me?

What if I'm not ready?

These 'what if's' can create endless loops in our minds, feeding anxiety, indecision, and over-

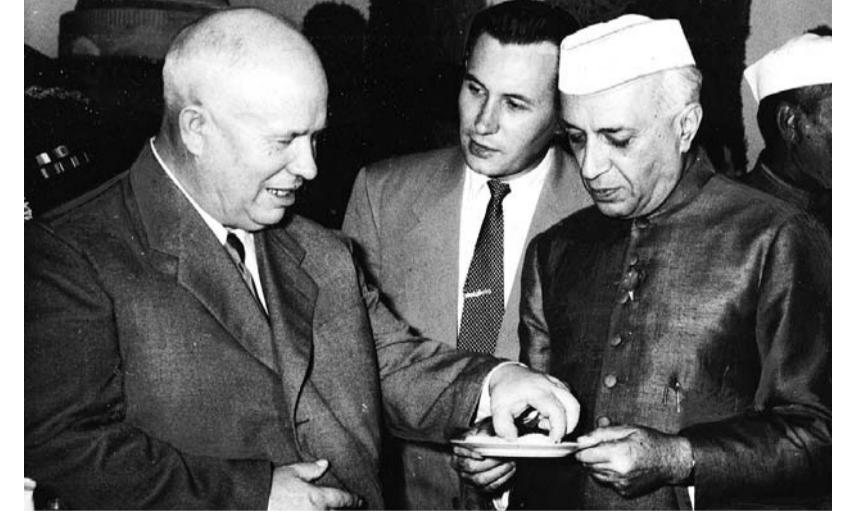
Fear Isn't the Enemy

It's important to say this clearly: fear itself is not the problem. It's a messenger; not a master. Fear evolved to protect us, and sometimes, it still does. But in our modern lives, it more often shows up when we're

From Circling Fear to Moving Through It

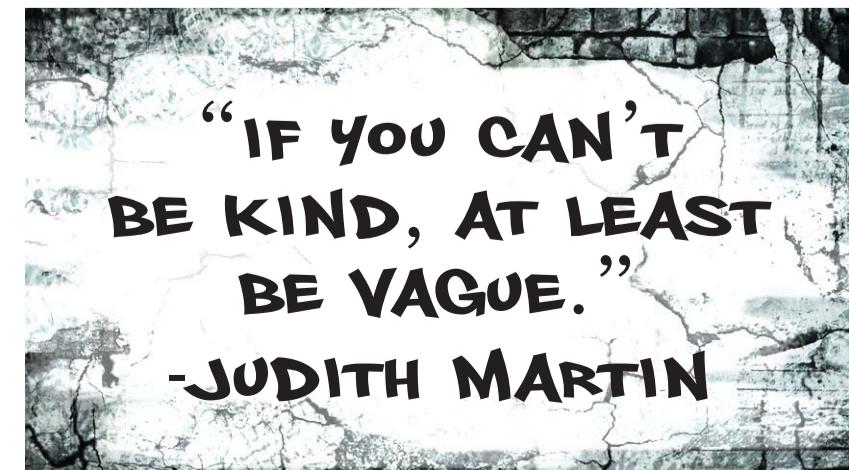
Most people spend their lives circling fear. We feel it rising, and we retreat. Or we overthink it. Or we numb it with distract-

about to grow, about to risk, or about to step outside our comfort zone. Suppressing fear doesn't make it go away. But honouring it and then choosing to move through it, that's where our strength is built.



Nehru with Nikita Khrushchev of the Soviet Union at Rashtrapati Bhavan in November 1955.

THE WALL



BABY BLUES



By Rick Kirkman & Jerry Scott

ZITS



By Jerry Scott & Jim Borgman



Inspiring Acts of Giving

Observed on September 5, the International Day of Charity promotes compassion, solidarity, and generosity across the globe. Established to honour the memory of Mother Teresa, it serves as a reminder that even small acts of kindness can make a big difference. The day encourages individuals, communities, and organisations to support causes that address poverty, hunger, education, and healthcare. From volunteering time to donating resources, it's an opportunity to foster a culture of empathy and shared responsibility. In an increasingly divided world, the International Day of Charity unites people through the universal language of giving and the hope it inspires.

O



Prime Minister Jawaharlal Nehru and Chinese Chairman Mao Zedong in Beijing.

#RISK

If You Didn't Get B.P. During Pregnancy...

Mothers at risk are over 35 years old, smokers, or delivered their baby via cesarean section

O ne in 10 women who did not have hypertension before or during pregnancy may develop it up to a year after they give birth, according to a new study.

People with no history of high blood pressure can develop hypertension for the first time in the weeks to months after childbirth, but until now, there has been very little data on first-time hypertension that develops more than six weeks after delivery.

The study, published in the journal *Hypertension*, also found that nearly a quarter of these cases of high blood pressure developed six weeks or more after childbirth. Mothers at highest risk are over 35 years old, current or former smokers, or patients who delivered their baby via cesarean section.

Nevertheless, he predicted that China's authoritarian system would outpace India. "There can be no question that within the next 10 or 20 years, China will far outstrip India in industrial development and in the mechanization of agriculture." He warned that India was destined to fall far behind "as long as China devotes five times as much of the national income to construction projects as India does."

The only way to prevent this, he argued, was if the West aided India's development. He noted that the Western bloc had allocated \$100 billion to paralyse what he called China's "iron fist." Even if just a hundredth of this amount was given to India as financial aid, he said, it would fortify its democracy.

"Indeed, because of India's high regard for the dignity and inviolability of the individual citizen, she might become a challenge, if not a threat, to totalitarian China, and serve as an example to other nations in Asia, which are still groping for a way out of their historical backwardness," he wrote.

Hindus' prediction did not materialise within the timeframe he envisioned. Over the next two decades, India and China struggled with internal challenges, including poverty. However, in 2025, the development gap between them is undeniable, and Western interest in positioning India as a counterbalance to China remains as strong as it was in the early 1950s.

Rajesh Sharma, author of *China's Edge*, Despite China's relative successes, Hindus acknowledged India's advantages, including its efficient civil service. "Neither Russia nor China has ever developed such a service or can hope to train one like it in the foreseeable future," he observed. "In consequence, the process of administration, whether in government or nationalised enterprises, is infinitely more competent and infinitely less costly in India than in China or Russia."

Another advantage India had was its access to Western science and technology. "There is no embargo on the sale of industrial equipment or even of strategic materials to India as there is to China," he said. "If India builds a steel plant or a tractor factory, it may do so accord-



times more common among non-Hispanic Black women compared to white women, she adds. "Understanding this relationship between pregnancy and hypertension is particularly important in addressing inequities in maternal cardiovascular disease and death for people of colour."

For the study, Parker and colleagues used medical records to examine demographic characteristics and prenatal, delivery, and postpartum data among 3,925 pregnant people who gave birth between 2016 and 2018 at Boston Medical Center.

The researchers analyzed patients' blood pressure measurements from the prenatal period through 12 months after delivery, taken at the hospital during office visits, urgent and emergency care, and readmissions.

The new study, which included racially and ethnically diverse participants, shows that patients with all three of the above risk factors have a 29% risk of developing new-onset postpartum hypertension, and that this risk increased to 36% among non-Hispanic Black patients.

This insight may provide a better understanding of the persistent racial disparities in US maternal morbidity and mortality, and the extent to which hypertension may contribute to these disparities. The findings also suggest strategies to identify and manage postpartum high blood pressure among high-risk patients before they are discharged from the hospital after delivery.

We were surprised at the number of cases captured more than six weeks after delivery, a period that falls well outside of routine postpartum follow-up," Parker says. "Monitoring during this period could mitigate severe postpartum and long-term cardiovascular complications."

Other studies suggest that new-onset hypertension after childbirth may be up to 2.5

Although the majority of patients were diagnosed with postpartum hypertension before they were discharged from the hospital following delivery, 43% of patients received first-time hypertension diagnoses after their delivery hospitalization, and about half of these new cases occurred more than six weeks postpartum, emphasizing the need for blood pressure monitoring throughout the entire postpartum period.

"Future research should explore opportunities to reduce the risk of hypertension in the postpartum period and investigate the implications of postpartum hypertension on future cardiovascular health."

Christina Rarington, assistant professor of obstetrics and gynecology at Chobanian & Avedisian School of Medicine is the study's senior author. Ayodele Ajayi, a research assistant at BUSPH at the time of the study, is a co-author.

I t's easy to say, "Don't be afraid." But that's not real life. Real courage comes from saying: "I see you, fear. You're trying to protect me. But I'm choosing a different path." That

path might be uncomfortable, but it leads to growth, clarity, and authentic living. You don't have to pretend that fear doesn't exist. You just don't have to let it decide your life."



